[2014] 13 एस.सी.आर. 1096

वी. श्रीरामचंद्रवधानी (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि

बनाम

शेख अब्दुल रहीम और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2364/2005)

21 अगस्त 2014

[जगदीश सिंह खेहर और रोहिंटन फली नरीमन, जेजे.]

मोहम्मडन कानून-उपहार (हिबा) - सशर्त उपहार - प्रकृति और प्रभाव – मोहम्मडन कानून के तहत, एक उपहार बिना शर्त होना चाहिए इसलिए, एक उपहार में व्यक्त की गई शर्तों को शून्य माना जाएगा - एक सशर्त उपहार वैध है, लेकिन शर्तें शून्य हैं हालाँकि, शर्तें स्वीकार्य हैं, यदि उपहार केवल एक सूदखोर का है - इसलिए, एक सूदखोर का उपहार वैध रूप से एक सीमा लगा सकता है, समय के संदर्भ में (ब्याज के रूप में, प्राप्तकर्ता के जीवन तक सीमित) - में एक उपहार जो निधि के हस्तांतरण पर विचार करता है, ऐसे हस्तांतरण के सशर्त होने का कोई सवाल ही नहीं है - हस्तांतरण पूर्ण है - निधि के उपहार में लगाई गई शर्तें शून्य हैं तथ्यों पर, विचाराधीन उपहार विलेख में निधि के हस्तांतरण पर विचार किया गया है न कि स्पष्ट रूप से, उपहार विलेख में दाता का इरादा, अचल संपत्ति के कोष को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना था, न कि केवल उसमें एक सूदखोर - चूंकि उपहार विलेख के माध्यम से दाता ने अचल संपत्ति के कोष को दानकर्ता को हस्तांतरित कर दिया था। प्राप्तकर्ता (उसकी पत्नी), उपहार विलेख वैध था-उपहार विलेख में उपहार में दी गई संपत्ति के उपयोग या निपटान को कम करने वाली सभी शर्तें शून्य थीं क्योंकि उपहार विलेख अपरिवर्तनीय रूप से अचल संपत्ति में सभी अधिकारों को प्राप्तकर्ता में निहित

करता है, बाद में बिक्री की जाती है प्राप्तकर्ता पत्नी द्वारा अपीलकर्ता को उपहार में दी गई अचल संपत्ति कानूनी और वैध थी, और परिणामस्वरूप, उपहार में दी गई संपत्ति पर उत्तरदाताओं का दावा था। प्राप्तकर्ता पत्नी के निधन पर, कानून में टिकाऊ नहीं है।

'एस', एक मुस्लिम सज्जन ने 26.04.1952 को एक उपहार विलेख निष्पादित किया, जिससे उसकी पत्नी 'बी' के पक्ष में एक अचल संपत्ति उपहार में दी गई। 'बी' ने 'एस' के जीवनकाल के दौरान संपत्ति का आनंद लिया; और 1966 में उनके निधन के बाद भी, संपत्ति का विशेष रूप से आनंद लेते रहे। 02.05.1978 को, 'बी' ने उपहार में दी गई संपत्ति अपीलकर्ता को बेच दी। 'बी' की मृत्यु 17.02.1989 को हो गई। उनके निधन पर, उत्तरदाताओं ने प्रतिशोधी-अपीलकर्ता को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने उक्त उपहार में दी गई संपत्ति पर दावा करते हुए कहा, सबसे पहले, कि उपहार में दी गई संपत्ति में 'बी' का केवल आजीवन हित था; और दूसरी बात यह कि 'एस' के एलआर होने के कारण उत्तरदाताओं को 'बी' की मृत्यु के बाद उपहार में दी गई संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व प्राप्त हो गया।

उत्तरदाताओं द्वारा दायर मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि 'एस' ने अचल संपत्ति का कोष अपनी पत्नी 'बी' को उपहार में दिया था; और उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 में दाता 'एस' द्वारा व्यक्त की गई सभी शर्तें, दान प्राप्तकर्ता 'बी' को उपहार में दी गई संपत्ति में पूर्ण अधिकार/हित से वंचित करने वाली सभी शर्तें शून्य थीं; और यह कि उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952, सूदखोरी की प्रकृति में नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं की कि क्या उपहार विलेख दिनांक 26-04-1952, संपत्ति के कोष का हस्तांतरण है, या केवल इसका उपभोग है; और माना कि 'बी' को 26.04.1952 को उपहार में दी गई संपत्ति में केवल जीवन भर का हित हस्तांतरित किया गया था। उच्च

न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि क्या उपहार अचल संपत्ति के कोष के संबंध में था, या उसके उपभोग के संबंध में था और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज निर्धारण की पुष्टि की।

तत्काल अपील में, विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 ने अपरिवर्तनीय रूप से 'बी' में अचल संपत्ति के सभी अधिकार निहित कर दिए, और इस प्रकार, 'बी' द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति की बिक्री 02.05 को अपीलकर्ता को कर दी गई। 1978, कानूनी और वैध था; और परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं का दावा 17.02.1989 को 'बी' के निधन पर उपहार में दी गई संपत्ति, कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. उपहारों के मानदंड (मोहम्मडन कानून के तहत) स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित हैं। मुहम्मडन कानून के तहत, उपहार बिना शर्त होना चाहिए। इसलिए, उपहार में व्यक्त शर्तों को शून्य माना जाएगा। एक सशर्त उपहार वैध है, लेकिन शर्तें शून्य हैं। [पैरा 11] [1109-जी; 1110-सी-डी]

1.2. संपत्ति के कोष से संबंधित उपहार पूर्ण हैं। जहां कॉर्पस का उपहार समय के संदर्भ में (जीवन हित के रूप में) एक सीमा लगाने का प्रयास करता है, वह शर्त शून्य है। इसी तरह, कॉर्पस के उपहार में अन्य सभी शर्तें अस्वीकार्य हैं। दूसरे शब्दों में, कॉर्पस का उपहार बिना शर्त होना चाहिए। हालाँकि, शर्तें स्वीकार्य हैं, यदि उपहार केवल उपभोग का है। इसलिए, सूदखोरी का उपहार वैध रूप से एक सीमा लगा सकता है, समय के संदर्भ में (ब्याज के रूप में, प्राप्तकर्ता के जीवन तक सीमित)। [पैरा 14] [1115-ई-एच]

1.3. एक उपहार में जो धनराशि के हस्तांतरण पर विचार करता है, ऐसे हस्तांतरण के सशर्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। स्थानांतरण पूर्ण है, कॉर्पस के उपहार में लगाई गई शर्तें शून्य हैं। [पैरा 15] [1116-ए-सी]

नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान, एआईआर 1948 पीसी 134-संदर्भित।

आसफ़ ए.फ़िज़ी आउटलाइन्स ऑफ़ मुहम्मदन लॉ", (पांचवां संस्करण, संपादित और संशोधित ताहिर महमूद, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस); "मुल्लाज़ प्रिंसिपल्स ऑफ़ महोमेडन लॉ (उन्नीसवां संस्करण, एम.हिदायतुल्लाह और अरशद हिदायतुल्लाह द्वारा) और "डाइजेस्ट ऑफ़ मुहम्मुडन लॉ", नील बी.ई. बैली द्वारा (भाग पहला, दूसरा संस्करण, लंदनः स्मिथ, एल्डर एंड कंपनी, 1875) – संदर्भित।

2. कॉर्पस का हस्तांतरण स्वामित्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि उपभोग का हस्तांतरण इसके उपयोग/आनंद आदि के अधिकार में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तथ्यों पर, उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 का पाठ हस्तांतरण पर विचार करता है कोष, न कि भोगफल। उपरोक्त निष्कर्ष के कारण इस प्रकार हैंः सबसे पहले, दाता ने उपहार में दी गई संपत्ति को अपनी कमाई से 16.07.1944 को एक पंजीकृत खरीद विलेख के माध्यम से खरीदा था, जिसके तहत उसे कब्जे और आनंद का पूर्ण अधिकार निहित था। संपत्ति। फिर यह दावा किया जाता है कि उपहार में दी गई संपत्ति पर दाता के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। दाता के उपरोक्त सभी अधिकार, उपहार के माध्यम से 'बी' को यह कहते हुए हस्तांतरित करने की मांग की जाती है, "मैं आपके पक्ष में संदेश दे रहा हूं क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं और आपसे प्यार करते हुए और आपको इसका अधिकार सौंप दिया है।" तुरंत, अब से आप इस अचल संपत्ति का

स्वतंत्र रूप से आनंद लेंगे......" यहां ऊपर दिए गए शब्द स्पष्ट रूप से उस निधि के हस्तांतरण को स्थापित करते हैं, जो दाता के पूर्ण स्वामित्व में था, प्राप्तकर्ता को। दूसरे, "हमें मूर्खतापूर्ण कारणों से इस हस्तांतरण को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा" शब्दों का उपयोग, दानकर्ता की संपत्ति के कोष को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करने के इरादे को भी प्रकट करता है। तीसरा, "न तो मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी इस हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में आपके या आपके उत्तराधिकारियों के खिलाफ कोई आपत्ति उठाएंगे" शब्दों का उपयोग प्राप्तकर्ता के साथ-साथ उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। ये शब्द न केवल संपत्ति में दाता के, बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी समाप्त कर देते हैं। दान प्राप्तकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को इस हद तक मान्यता दी गई है कि उपहार में दी गई संपत्ति दान प्राप्तकर्ता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होने की स्थिति में दानकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। यह दानकर्ता की संपत्ति दान की गई राशि को हस्तांतरित करने के इरादे को भी दर्शाता है। चौथा, उपहार विलेख में दर्ज है कि "... आपके जीवन काल के बाद यह संपत्ति आपके वसंत ऋतु में हस्तांतरित हो जाएगी..."। "आपका ऑफ स्प्रिंग" शब्दों का उपयोग एक इरादे को व्यक्त करता है जो "हमारे ऑफ स्प्रिंग" से अलग और अलग है। दूसरे शब्दों में, उपहार विलेख उपहार में दी गई संपत्ति को प्राप्तकर्ता द्वारा अपने बच्चों को हस्तांतरित करने पर विचार करता है, भले ही ऐसे बच्चे दाता के बच्चे न हों। इससे यह भी पता चलता है कि दानकर्ता की मंशा, निधि के हस्तांतरण पर विचार करना था। पांचवें, उपहार विलेख में लिखा है, "मैं राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम परिवर्तित कराने के लिए पंजीकरण के लिए इस विलेख के साथ स्थानांतरण ज्ञापन दाखिल कर रहा हूं। इसलिए अब से आप नगरपालिका करों का भुगतान करेंगे और स्वतंत्र रूप से और खुशी से इसका आनंद लेंगे।" उपहार विलेख में यह अभिव्यक्ति, दाता के इरादे को उजागर करती है, कि उपहार

में दी गई संपत्ति का हस्तांतरण परिवार के भीतर समझ का विषय नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के लिए एक खुली घोषणा होनी चाहिए। उपहार विलेख में दावा, कि नगरपालिका कर दान प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा, यह दर्शाता है कि दान प्राप्तकर्ता को अब से उपहार में दी गई संपत्ति की सभी देनदारियों को उसके मालिक के रूप में वहन करना होगा। अंत में, उपहार विलेख में यह दर्ज करके कि "मैंने लिंक बिक्री विलेख और वाउचर आपको सौंप दिया है" उपहार में दी गई संपत्ति के पहले स्वामित्व विलेख को प्राप्तकर्ता को सौंपना भी इंगित करता है, कि दाता ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है उपहार विलेख, कि उसने उपहार में दी गई संपत्ति से संबंधित स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज अपने पास नहीं रखा था, बल्कि उसे प्राप्तकर्ता को सौंप दिया था। इससे दाता के उपहार में दिए गए अपने सभी मौजूदा अधिकारों को त्यागने के इरादे का भी पता चलता है। इससे दाता के इरादे का भी पता चलता है कि वह संपत्ति की राशि प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना चाहता है। स्पष्ट रूप से, उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 में दाता का इरादा, अचल संपत्ति के कोष को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना था, न कि केवल उसमें एक सूदखोरी.. [पैरा 16] [1116-डी-ई; 1117-एफ-एच; 1118-ए-एच; 1119-ए-डी]

3. चूंकि दाता 'एस' ने उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 के माध्यम से अचल संपत्ति का कोष अपनी पत्नी 'बी' को हस्तांतरित कर दिया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि उपहार विलेख 'बी' के पक्ष में निष्पादित किया गया था। वैध। इसी तरह, उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 में दर्शाई गई सभी शर्तें, जो ई द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति के उपयोग या निपटान को कम करती हैं, को शून्य माना जाएगा। मामले के उपरोक्त दृश्य में, उपहार विलेख में दर्शाई गई शर्तें, कि दान प्राप्तकर्ता को उपहार में दी गई संपत्ति को उपहार में देने या बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा, या दान प्राप्तकर्ता को उसके जीवन काल के दौरान उपहार में दी गई अचल संपत्ति को

हस्तांतरित करने से रोका जाएगा, शून्य हैं. इसी प्रकार, उपहार विलेख में दर्शाया गया है कि उपहार में दी गई अचल संपत्ति प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद उसे तुरंत हस्तांतरित हो जाएगी और उसके कोई संतान नहीं होने की स्थिति में, वह दानकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी। , वैसे ही शून्य होगा. [पैरा 17] [1119-डी-एच; 1120-ए]

4. चूँकि उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 ने अपरिवर्तनीय रूप से 'बी' में अचल संपत्ति के सभी अधिकार निहित कर दिए, यह स्पष्ट है कि 'बी' द्वारा 02.05.1978 को अपीलकर्ता को उपहार में दी गई अचल संपत्ति की बिक्री कानूनी और वैध थी। नतीजतन, 17.02.1989 को 'बी' की मृत्यु पर, उपहार में दी गई संपत्ति पर उत्तरदाताओं का दावा कानून में टिकाऊ नहीं है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। [पैरा 18][1120-ए-सी]

केस कानून संदर्भ

एआईआर 1948 पीसी 134 संदर्भित पैरा 6

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2364/2005

उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के 2004 की दूसरी अपील संख्या 313 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.08.2004 से।

जी. रामकृष्ण प्रसाद और वेंकट सुब्रमण्यन, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं के लिए।

ए. सुब्बा राव, सुदीप्तो सिरकार (अन्नम डी.एन. राव के लिए), वेंलेटेश्वर राव अनुमोलु और प्रभाकर परनाम, वकील, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का फैसला जगदीश सिंह खेहर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

2. शेख हुसैन का विवाह बानू बीबी से हुआ था। अपने वैवाहिक संबंधों के निर्वाह के दौरान, शेख हुसैन ने 26.04.1952 को एक उपहार विलेख निष्पादित किया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के एलुरु शहर में सर्वेक्षण संख्या 883 में खुली जगह वाला एक "टाइल वाला घर" उनकी पत्नी बानू बीबी के पक्ष में उपहार में दिया गया था।

3. इसमें कोई विवाद की बात नहीं है कि बानू बीबी ने अपने पति शेख हुसैन के जीवनकाल के दौरान उन्हें उपहार में दी गई अचल संपत्ति का आनंद लिया, शेख हुसैन की 1966 में मृत्यु हो गई। शेख हुसैन के निधन के बाद भी, बानू बीबी ने विशेष रूप से आनंद लेना जारी रखा। उक्त अचल संपति. 02.05.1978 को, बानू बीबी ने उपहार में दी गई अचल संपत्ति वी. श्रीरामचंद्र अवधानी को बेच दी। प्रतिवादी वी श्रीरामचंद्र अवधानी इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं (अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से)।

4. बानू बीबी की मृत्यु 17.02.1989 को हुई। उनके निधन पर, इस अदालत के प्रतिवादियों-शैल अब्दुल रहीम और शेख अब्दुल गफूर ने प्रतिवादी को कानूनी नोटिस जारी किया। कानूनी नोटिस के माध्यम से, उन्होंने उपर्युक्त उपहार में दी गई अचल संपत्ति पर दावा ठोक दिया। नोटिस में, उत्तरदाताओं ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि उपहार में दी गई अचल संपत्ति में बानू बीबी का केवल आजीवन हित था; और दूसरी बात, उत्तरदाताओं को शेख हुसैन (जिन्होंने बानू बीबी को अचल संपत्ति उपहार में दी थी) के कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते निहित किया गया। उपहार में दी गई अचल संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व के साथ, बाद में बानू बीबी का निधन. प्रतिशोधी, वी.श्रीरामचंद्र अवधानी ने कानूनी नोटिस में किए गए दावों को खारिज कर दिया। दिनांक 22.03.1989, अपनी प्रतिक्रिया दिनांक 16.04.1989 के माध्यम से।

5. यह महसूस करने के बाद कि प्रतिवादी बानू बीबी से खरीदी गई अचल संपत्ति को नहीं छोड़ेगा, उत्तरदाताओं ने अधीनस्थ न्यायाधीश, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश के समक्ष 1989 के ओएस नंबर 256 वाले एक मुकदमे को प्राथमिकता दी। मुकदमे में, उत्तरदाताओं ने खुली जगह वाले "टाइल वाले घर" पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की, जिसे शेख हुसैन ने अपनी पत्नी बानू बीबी को उपहार में दिया था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने प्रतिवादी वी. श्रीरामचंद्र अवधानी से कब्जे की वसूली और मेस्ने मुनाफे की भी मांग की। 13.11.1989 को दायर उपरोक्त मूल मुकदमे का विरोध किया गया था। 19.07.1990 को एक लिखित बयान दायर किया गया था।

6. प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश ने 19.08.1998 को मूल मुकदमा खारिज कर दिया। नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान, एआईआर 1948 पीसी 134 में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शेख हुसैन द्वारा 26.04.1952 को निष्पादित उपहार विलेख अचल संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित करता है। उनकी पत्नी बानू बीबी वैध थीं। यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि उपहार में दी गई अचल संपत्ति अपरिवर्तनीय रूप से प्राप्तकर्ता बानू बीबी में निहित हो गई। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने माना कि शेख हुसैन ने अपनी पत्नी बानू बीबी को अचल संपत्ति का उपहार दिया था। पूर्वोक्त के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 में दाता शेख हुसैन द्वारा व्यक्त की गई सभी शर्तें, उपहार प्राप्तकर्ता को उपहार में दी गई संपत्ति में पूर्ण अधिकार/हित से वंचित करती हैं, शून्य थीं। ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि दिनांक 26.04.1952 का उपहार विलेख, सूदखोरी की प्रकृति में नहीं था।

7. ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, उत्तरदाताओं ने द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश के समक्ष अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 05.01.2004 को उत्तरदाताओं द्वारा की गई अपील को स्वीकार कर लिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस मुद्दे पर कि क्या बानू बीबी को उपहार में दी गई खुली जगह वाले "खपरैल वाले घर" पर पूर्ण अधिकार था। दिनांक 26.04.1952 के उपहार विलेख के पाठ के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए विचार को यहां निकाला जा रहा है।

> "13. यह साबित करना वादी का परम कर्तव्य है कि उन्हें शेख हुसैन साहब के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति विरासत में मिली है, क्योंकि उनकी पत्नी को संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है। उदाहरण ए-1 और बी-5 जो एक है और सरने दस्तावेज़ इस मुकदमे में मुख्य मुद्दे को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। उक्त दस्तावेज़ के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त समझौता विलेख दिनांक 26-4-1952 में जिसे शेख हुसैन साहब ने अपने पक्ष में निष्पादित किया था पत्नी भानुबीबी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि, उन्हें संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है और वह अपनी इच्छानुसार संपत्ति का आनंद ले सकती हैं और उनकी मृत्यु के बाद यह उनके बच्चों को हस्तांतरित होगा यदि उनके बच्चे हैं और यदि उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनके उत्तराधिकारी होंगे। शेख हुसैन साहब को वही विरासत मिलेगी, यह उक्त दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से इस प्रकार उल्लिखित है:

"अपने जीवन काल के दौरान आप इस संपत्ति को किसी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं करेंगे और आपके जीवन काल के बाद यह संपत्ति आपके संतान होने पर हस्तांतरित हो जाएगी और यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो यह संपत्ति मुझे या मेरे निकटतम उत्तराधिकारियों को पूर्ण अधिकार के साथ वापस मिल जाएगी उपहार, बिक्री आदि के माध्यम से आनंद और बेदखली का।"

इस पाठ से पता चलता है कि, भानुबीबी को वादी अनुसूची की संपत्ति को अलग करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें केवल जीवन भर इसका आनंद लेने का अधिकार है और उनकी मृत्यु के बाद, यदि उनके बच्चे होते हैं और बच्चों की अनुपस्थिति में, यह उनके बच्चों को हस्तांतरित हो जाएगा। यह उनके पति शेख हुसैन साहब के पास वापस आ जाएगा और भानुबीबी की कोई संतान नहीं है। इसके अलावा माना जाता है कि शेख हुसैन साहब की मृत्यु पहले हुई थी। भानुबीबी. इसके अलावा यह भी स्वीकार किया गया कि वादी कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

शेख हुसैन साहब. उपरोक्त समझौता विलेख के अनुसार, वादी, वादी अनुसूची संपत्ति के असली मालिक हैं। इसके अलावा, हालांकि प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कुछ अन्य संपत्ति के लिए शेख हुसैन साहब ने एक वसीयत की थी और वादी ने एक मुकदमा दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था, उक्त तथ्य इस मामले के तथ्यों और कार्रवाई के कारण और इसमें शामिल संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं। मुकदमे में अलग-अलग हैं और इसके अलावा 1 "प्रतिवादी ने

> अपने अधिकार की पुष्टि के लिए उक्त का कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। इसलिए यह न्यायालय मानता है कि, वादी संपत्ति के पूर्ण मालिक हैं और वे मुकदमे की अनुसूची संपत्ति की घोषणा के हकदार हैं .इसलिए इस मुद्दे का निर्णय वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।"
>
> (हमारा जोर है।)

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि अपील पर फैसला सुनाया गया था, जैसे कि विवाद तथ्य के विवादित प्रश्न की प्रकृति में था, मुहम्मदन कानून के तहत उपहार से संबंधित कानूनी निहितार्थों की सराहना किए बिना। विवाद का निर्धारण करते समय, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं की कि क्या दिनांक 26.04.1952 का उपहार, संपत्ति के कोष का हस्तांतरण है, या केवल इसका उपभोग है। प्रथम अपीलीय न्यायालय, ट्रायल कोर्ट द्वारा भरोसा किए गए प्रिवी काउंसिल के फैसले के संदर्भ के बिना, 26.04.1952 के उपहार विलेख के पाठ की व्याख्या करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बानू बीबी को केवल जीवन हित हस्तांतरित किया गया था खुली जगह वाले "टाइल वाले घर" में, 26.04.1952 को उन्हें उपहार में दिया गया।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट, प्रतिवादी वी. श्रीरामचंद्र अवधानी ने हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय (इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 02.08.2004 को 2004 की द्वितीय अपील संख्या 313 का निपटारा करते हुए पुष्टि की। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रिकार्ड निर्धारण किया गया। उपहार विलेख दिनांक

26.04.1952 की प्रकृति और प्रभाव पर उच्च न्यायालय के आदेश का ऑपरेटिव भाग यहां नीचे दिया जा रहा है:

> "की गई दलीलों और सामग्री के अवलोकन पर विचार करते हुए, इस अपील में जो सवाल विचाराधीन है, वह यह है कि क्या भानुबीबी शेख हुसैन साहब की पत्नी हैं, जो कथित तौर पर संपत्तियों के मालिक थे, और उनके पास कोई अलग अधिकार था 26-04-1952 को उसके पक्ष में निष्पादित निपटान विलेख की शर्तें और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री वैध है। आवश्यक रूप से, ये प्रश्न निपटान विलेख के नियमों और शर्तों और उसकी व्याख्या पर विचार करने के लिए कहते हैं, जो नहीं संदेह एक तथ्यात्मक मैट्रिक्स है। उक्त निपटान विलेख में निहित शर्तों के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। निचली अपीलीय अदालत ने उस पर लगाए गए प्रतिबंध पर विचार किया और कहा कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं है और वादी हैं केवल उत्तराधिकारी, यह माना गया कि अपीलकर्ता के पक्ष में बिक्री नहीं हो सकती थी। उसमें निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए और जिस पर निचली अपीलीय अदालत ने सही ढंग से विचार किया है, मुझे इस संबंध में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली उक्त निपटान विलेख की शर्तों पर विचार करने में निचली अपीलीय अदालत द्वारा किए गए दृष्टिकोण के अनुसार।"

(हमारा जोर है।)

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए विचार के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने उपहार की प्रकृति और प्रभाव की भी जांच नहीं की। इसमें इस बात

पर विचार नहीं किया गया कि क्या उपहार अचल संपत्ति के कोष के संबंध में था, या उसके उपभोग के संबंध में था। उच्च न्यायालय ने नवाजिश अली खान के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए फैसले पर भी विचार नहीं किया (विचारण न्यायालय जिस पर भरोसा किया गया था)। उपहार विलेख (दिनांक 26.04.1952) में व्यक्त नियमों और शर्तों की शाब्दिक व्याख्या के आधार पर विवाद का फिर से निपटारा किया गया।

9. प्रथम अपीलीय न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय के समक्ष हारने के बाद, प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों ने 2004 की विशेष अपील अपील (सिविल) संख्या 22023 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय द्वारा 01.04.2005 को अनुमति दी गई थी।

10. हमने प्रतिद्वंद्वी पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वान वकील को सुना है। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने उपहार (हिबा) के विषय पर मुहम्मदन कानून के विभिन्न पहलुओं पर भरोसा जताया। इस संबंध में संदर्भ सबसे पहले "आसफ़ ए.ए. फ़िज़ी आउटलाइन्स ऑफ़ मुहम्मदन लॉ" (पांचवें संस्करण, ताहिर महमूद, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा संपादित और संशोधित) पर रखा गया था। "सशर्त उपहार" के विषय पर, मुहम्मदन कानून के मूल सिद्धांतों/सिद्धांतों को इस ग्रंथ में समझाया गया है।

> "शर्तों के साथ उपहार
>
> हिबा में किसी वस्तु के पदार्थ या कोष में तत्काल और पूर्ण स्वामित्व प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है; इसलिए जहां हिबा को इसके उपयोग या निपटान के संबंध में शर्तों या प्रतिबंधों के

साथ बनाया जाना चाहिए, वहां शर्तें और प्रतिबंध शून्य हैं और हिबा वैध है। फतवा आमगिरी कहता है:

हमारे सभी 'मालिक' इस बात पर सहमत हैं कि जब किसी ने उपहार दिया है और ऐसी शर्त रखी है जो फासीद या अमान्य है, तो उपहार वैध है और शर्त शून्य है। यह उन सभी अनुबंधों के संबंध में एक सामान्य नियम है जिनमें सीज़िन की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपहार और प्रतिज्ञा करें, कि वे परिस्थितियों को बिगाड़ने के कारण अमान्य नहीं होंगे।

उदाहरण:-

(1) डी निवास के लिए एक घर का हिबा बनाता है। प्राप्तकर्ता और उसके उत्तराधिकारी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, यह घोषणा करते हैं कि यदि प्राप्तकर्ता इसे बेचता है या गिरवी रखता है तो दाता या उसके उत्तराधिकारियों का घर पर दावा होगा, अन्यथा नहीं। प्राप्तकर्ता हनफ़ी और इथना अशारी कानून दोनों में पूर्ण संपत्ति लेता है।

(ii) डी इस शर्त पर हिबा बनाता है कि उसके पास तीन दिनों के भीतर हिबा को रद्द करने का विकल्प है। हिबा वैध है और विकल्प शून्य है।

(iii) ए, बी को सरकारी वचन पत्र का उपहार इस शर्त पर देता है कि बी को नोटों का एक-चौथाई हिस्सा एक महीने के बाद ए को वापस करना होगा। यह शर्त धनराशि के एक हिस्से की वापसी से संबंधित है। शर्त शून्य है और उपहार वैध है।

(iv) ए कुछ संपत्ति का हिबा बी को देता है। उपहार विलेख में यह शर्त होती है कि बी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करेगा। स्थानांतरण के विरुद्ध प्रतिबंध शून्य है और बी पूरी तरह से संपत्ति लेता है।"

(हमारा जोर है।)

रिलायंस को "मुल्ला के महोमेदान कानून के सिद्धांतों (एम.हिदायतुल्ला और अरशद हिदायतुल्ला द्वारा उन्नीसवां संस्करण) पर भी रखा गया था और हमारा ध्यान निम्नलिखित कथन की ओर आकर्षित किया गया था:

"एक शर्त के साथ उपहार - जब कोई उपहार ऐसी शर्त के अधीन किया जाता है जो अनुदान की पूर्णता को कम करता है, तो शर्त शून्य है, और उपहार ऐसे प्रभावी होगा जैसे कि उसके साथ कोई शर्तें जुड़ी नहीं थीं"

"हमारे सभी स्वामी इस बात पर सहमत हैं कि जब किसी ने एक उपहार दिया है और एक ऐसी शर्त निर्धारित की है जो फासीद या अमान्य है, तो उपहार वैध है और शर्त शून्य है"।

जीवन-संपदा का उपहार - जीवन-संपत्ति को इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता था, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता पूर्ण रुचि लेता था। लेकिन अमजद खान केस (1929) 56 1.ए.213, 4 लक.305 न्यायिक समिति ने सिद्धांत को तथ्यों पर लागू नहीं माना। 55 सेकंड देखें. और वहां के मामलों का हवाला दिया गया।

"एक आम्री (जीवन अनुदान) एक उपहार और एक शर्त के अलावा और कुछ नहीं है, और यह शर्त अमान्य है; लेकिन एक अमान्य शर्त शामिल करने से उपहार शून्य नहीं हो जाता है। हेदाया,

489। बाद के मामले में प्रिवी काउंसिल (नवाज़िश अली खान बनाम अली रज़ा खान (1948) 75 1.ए.62, (48) ए.पीसी.134) ने देखा कि मुस्लिम कानून में जीवन संपत्ति या निहित शेष जैसी कोई चीज नहीं थी जैसा कि अंग्रेजी कानून में समझा जाता है, बल्कि एक उपहार है जीवन को सुखभोग में जीवन के हित के रूप में समझा जाएगा। 'जीवन संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण ही प्राप्तकर्ता के जीवन तक सीमित है

इस शर्त के साथ कि प्राप्तकर्ता को अलगाव का कोई अधिकार नहीं होगा, मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन यह दृष्टिकोण एक बार इस प्रभाव पर हावी हो गया कि मुस्लिम कानून के तहत,

ऐसी स्थिति के साथ जीवन हित एक प्रतिकूल स्थिति के साथ एक उपहार के अलावा और कुछ नहीं है, जब शर्त विफल होनी चाहिए और उपहार को पूर्ण रूप से प्रबल होना चाहिए, यह नहीं है प्रिवी काउंसिल के बाद के निर्णयों के मद्देनजर अब अच्छा कानून बन गया है।"

(हमारा जोर है।)

यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रिवी काउंसिल या किसी अन्य न्यायालय द्वारा व्यक्त किसी भी विपरीत कानूनी दृष्टिकोण पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था।

11. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने नील बी.ई.बैली (भाग पहला, दूसरा संस्करण, लंदनः स्मिथ, एल्डर एंड कंपनी, 1875) द्वारा लिखित "डाइजेस्ट ऑफ

मोहुम्मुडन लॉ" पर भी भरोसा किया। जिस पाठ पर भरोसा किया गया है उसका प्रासंगिक उद्धरण है यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "उपहार दो प्रकार के होते हैं, तुमलीक (पहले से ही वर्णित), और इस्कत, जिसका शाब्दिक अर्थ है, गिराना, या बुझाना. उपहार के कानूनी प्रभाव हैं- 1. यह दाता पर अनिवार्य हुए बिना, प्राप्तकर्ता में संपत्ति का अधिकार स्थापित करता है, ताकि उपहार को वैध रूप से फिर से शुरू किया जा सके या रद्द किया जा सके। 2. यह कि इसे किसी शर्त के अधीन नहीं बनाया जा सकता है, हालाँकि यदि उपहार प्राप्तकर्ता को तीन दिनों के विकल्प के साथ दिया गया था, और पार्टियों के अलग होने से पहले स्वीकार कर लिया गया था, तो यह वैध होगा। और 3डी यह कि परिस्थितियों को बिगाड़कर इसे रद्द नहीं किया गया है; ताकि यदि कोई अपने दास को मुक्ति की शर्त पर दे, तो उपहार वैध होगा, और शर्त व्यर्थ होगी।"
>
> (हमारा जोर है।)

उपरोक्त पाठ के अवलोकन से अन्य बातों के साथ-साथ पता चलता है कि मुहम्मदी कानून के तहत, एक उपहार बिना शर्त होना चाहिए। इसलिए, उपहार में व्यक्त शर्तों को शून्य माना जाएगा। एक सशर्त उपहार वैध है, लेकिन शर्तें शून्य हैं।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान नील बी.ई.बैली द्वारा लिखित "डाइजेस्ट ऑफ मोहुम्मुडन लॉ" के दूसरे भाग की ओर आकर्षित किया, जो "उपहार में एक शर्त के प्रभाव" से संबंधित है। जिस पाठ पर भरोसा किया गया है उसे यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"जब कोई दास या वस्तु इस शर्त पर दी जाती है कि प्राप्तकर्ता के पास तीन दिनों के लिए विकल्प होगा, तो उपहार वैध है यदि पार्टियों के अलग होने से पहले उसके द्वारा पुष्टि की गई है; और यदि उनके अलग होने के बाद तक उसके द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, यह वैध नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ इस शर्त पर दी जाती है कि दाता के पास तीन दिनों के लिए विकल्प होगा, तो उपहार वैध है, और विकल्प शून्य है; क्योंकि उपहार एक बाध्यकारी अनुबंध नहीं है, और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। शर्त का विकल्प। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, 'मैंने तुम्हें तुम्हारे विरुद्ध अपने अधिकार से मुक्त कर दिया है, इस शर्त पर कि मेरे पास एक विकल्प है, रिहाई वैध है, और विकल्प शून्य है।

एक आदमी जिस पर एक हजार दिरहम बकाया है, उससे कहता है, "जब कल आ जाएँगे हजार तुम्हारे हैं, या तुम उससे मुक्त हो,' या 'जब तुमने संपत्ति का आधा हिस्सा चुका दिया है तो तुम शेष आधे से मुक्त हो,' या 'शेष आधा तुम्हारा है,' उपहार शून्य है। परन्तु यदि वह कहे, "मैंने तुम्हें इस शर्त पर छोड़ा है कि तुम अपने दास को मुक्त करोगे, या तुम इस शर्त पर रिहा हुए हो कि तुम उसे मेरे मुक्त करने से मुक्त करोगे, और वह कहे, 'मैंने स्वीकार कर लिया है, या 'मैंने उसे मुक्त कर दिया है।", वह कर्ज से मुक्त हो जाएगा।

सभी 'हमारे' स्वामी इस बात पर सहमत हैं कि जब किसी ने उपहार दिया है और ऐसी शर्त रखी है जो फासीद या अमान्य है, तो उपहार वैध है और शर्त शून्य है; जैसे कि किसी को दूसरे को एक

दासी देनी चाहिए, और यह शर्त लगानी चाहिए कि 'वह उसे नहीं बेचेगा, या 'उसे को-इ-वुलूद नहीं बनाएगा,' या 'उसे ऐसे किसी को बेच देगा,' या 'उसे वापस लौटा देगा' एक महीने के बाद देने पर उपहार वैध होगा और सभी शर्तें शून्य हो जाएंगी। या अगर किसी को एक हवेली देनी चाहिए, या इसे भिक्षा में देना चाहिए, इस शर्त पर कि प्राप्तकर्ता इसका कुछ हिस्सा वापस कर देगा,' या 'इसमें से कुछ हिस्सा इवुज़ दे, या विनिमय करें, तो उपहार वैध होगा और शर्त शून्य होगी। ' यह उन सभी अनुबंधों के संबंध में एक सामान्य नियम है, जिनमें सीज़िन की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपहार और गिरवी, कि वे शर्तों को बिगाड़ने के कारण अमान्य नहीं होते हैं।"

(हमारा जोर है।)

उपरोक्त पाठ से भी वही निष्कर्ष निकलते हैं जो ऊपर निकाले गए हैं।

13. ऊपर देखी गई विभिन्न टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमारा ध्यान नवाज़िश अली खान के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि उनके द्वारा हमारे ध्यान में लाए गए पाठ को उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से अनुमोदित किया गया था। विद्वान वकील ने नवाजिश अली खान के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के फैसले से निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा जताया:

"19 अपील में मुख्य न्यायालय ने यह विचार किया कि नासिर अली खान की वसीयत के तहत संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद जीवन भर के लिए लगातार तीन किरायेदारों में निहित हो गई; कि नियुक्ति की शक्ति के प्रयोग पर यह तुरंत नियुक्त व्यक्ति के पास चली जाएगी; ऐसी कोई

अवधि नहीं थी जिसके दौरान संपत्ति स्थगित रहेगी; और वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित या पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं थे। उनके आधिपत्य की राय में मामले का यह दृष्टिकोण मुस्लिम कानून में कानूनी शर्तों और स्वामित्व की अवधारणाओं से काफी परिचित है अंग्रेजी कानून में, लेकिन मुस्लिम कानून से पूरी तरह अलग। सामान्य तौर पर, मुस्लिम कानून वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं करता है, और उनके आधिपत्य को मुस्लिम कानून पर किसी भी आधिकारिक कार्य के बारे में पता नहीं है, चाहे हेदया या बैली या अधिक आधुनिक कार्य , और इस बोर्ड का कोई निर्णय नहीं है जो पुष्टि करता है कि मुस्लिम कानून भूमि के स्वामित्व को संपत्तियों में विभाजित करने को मान्यता देता है, कानूनी और न्यायसंगत संपत्तियों की तरह गुणवत्ता के मामले में प्रतिष्ठित है, या अवधि के बिंदु पर संपत्ति की तरह शुल्क सरल, पूंछ में, जीवन के लिए , या शेष में. मुस्लिम कानून जिस बात को मान्यता देता है और उस पर जोर देता है, वह है संपत्ति के कोष (अयन) और संपत्ति में भोग (मनाफ़ी) के बीच का अंतर। संपत्ति के कोष पर कानून केवल पूर्ण प्रभुत्व, वंशानुगत और समय के संदर्भ में अप्रतिबंधित को मान्यता देता है, और जहां कोष का उपहार ऐसे पूर्ण प्रभुत्व के साथ असंगत स्थिति को लागू करने का प्रयास करता है, तो शर्त को प्रतिकूल के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन हित संपत्ति के उपभोग में सीमित समय का सृजन किया जा सकता है और कोष पर प्रभुत्व ऐसे किसी भी सीमित हितों के अधीन प्रभावी होता है।

"यदि कोई व्यक्ति अपने दास की सेवा, या अपने घर का उपयोग, या तो एक निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए करता है, तो ऐसी वसीयत वैध है; क्योंकि भोग के साथ बंदोबस्ती के रूप में, या तो मुफ्त या समकक्ष के लिए, जीवन के दौरान वैध है , परिणामस्वरूप मृत्यु के बाद भी ऐसा ही होता है; और, क्योंकि पुरुषों के पास इस प्रकृति की वसीयत के साथ-साथ वास्तविक संपत्ति की वसीयत करने का भी अवसर होता है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति अपने दास की मजदूरी, या अपने घर का किराया, एक निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए वसीयत करता है, तो यह उसी कारण से वैध है। इसके अलावा, दोनों मामलों में, घर या दास को विरासती को सौंपना आवश्यक है, बशर्ते कि वे संपत्ति के एक तिहाई से अधिक न हों ताकि वह दास की मजदूरी या सेवा, या किराया या का आनंद ले सके। घर का उपयोग करने के लिए निर्धारित अवधि का साहस करें, और बाद में इसे उत्तराधिकारियों को बहाल करें।" (हेडया, खंड 4, पृष्ठ 527, अध्याय 5, जिसका शीर्षक है "ऑफ यूसुफ्रक्चुअरी विल।"

यह भेद उपहारों के मुस्लिम कानून में चलता है - कॉर्पस (हिबा) के उपहार, सूदखोरी (अरियात) के उपहार और सूदभोगी वसीयतें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां घर का उपयोग किसी व्यक्ति को उसके जीवन भर के लिए दिया जाता है, तो उसे अनुचित रूप से नहीं, जीवन भर के लिए किरायेदार कहा जा सकता है, और घर का मालिक, सीमित ब्याज की समाप्ति तक इसका आनंद लेने की प्रतीक्षा कर सकता है। कहा, गलत तरीके से नहीं, निहित शेष रखने के लिए। हालाँकि, समान चीजों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी और मुस्लिम

कानून में समान शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, कानून की दो प्रणालियाँ स्वामित्व की बिल्कुल अलग अवधारणाओं पर आधारित हैं। अंग्रेजी कानून भूमि के स्वामित्व को सीमित अवधि के लिए मान्यता देता है, मुस्लिम कानून केवल असीमित अवधि के स्वामित्व को स्वीकार करता है, लेकिन संपत्ति के उपयोग में सीमित अवधि के हितों को मान्यता देता है।

20 अमजद खान बनाम अशरफ खान के मामले में सर वज़ीर हसन के फैसले में इस विषय पर कानून की पूरी चर्चा है। 4 उस मामले ने हनफ़ी वकीलों द्वारा स्वीकार किए गए सिद्धांत को चुनौती दी कि जीवन के लिए "ए" को एक उपहार "ए" पर पूर्ण ब्याज प्रदान करता है; पैगंबर के एक कथन पर आधारित एक सिद्धांत (हेदया, बीके. III, पृष्ठ 309):

"एक अमरी या जीवन अनुदान अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए उसके जीवन के दौरान वैध है और उसके उत्तराधिकारियों को मिलता है। अमरी का अर्थ प्राप्तकर्ता के जीवन के दौरान एक घर का उपहार है (उदाहरण के लिए), इस शर्त पर कि यह उसकी मृत्यु पर वापस कर दिया जाएगा. एक अम्री एक उपहार और एक शर्त के अलावा और कुछ नहीं है और शर्त अमान्य है, लेकिन एक उपहार अमान्य शर्त को शामिल करके अमान्य नहीं किया जाता है।"

सर वज़ीर हसन ने अपने फैसले में प्रिवी काउंसिल के उचित परीक्षणों और सभी प्रासंगिक निर्णयों की जांच की। उन्होंने मुस्लिम कानून में कॉर्पस और सूदखोरी के बीच, वस्तु और वस्तु के उपयोग के बीच

अंतर बताया। उस विलेख के निर्माण पर, जो उसके सामने मामले में विचाराधीन था, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दाता अपनी पत्नी को धन नहीं, बल्कि केवल जीवन हित प्रदान करना चाहता था, कि ऐसा जीवन हित उपहार के रूप में प्रभावी हो सकता है संपत्ति के उपयोग के बारे में, न कि संपत्ति के हिस्से के रूप में, और मुस्लिम कानून में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे यह मानने के लिए मजबूर करता हो कि जीवन संपत्ति का इच्छित उपहार, प्राप्तकर्ता पर पूर्ण ब्याज प्रदान करता है। यह मामला प्रिवी काउंसिल में अपील के रूप में लिया गया था और 56 आईए 213.5 में रिपोर्ट किया गया है। बोर्ड ने सर वजीर हसन के साथ विचाराधीन विलेख के निर्माण पर सहमति व्यक्त की थी कि केवल जीवन हित का इरादा था, और माना कि यदि पत्नी केवल जीवन लेती है ब्याज उसकी मृत्यु पर समाप्त हो गया और अपीलकर्ता, जो उसका उत्तराधिकारी था, ने कुछ भी नहीं लिया, और यदि जीवन हित बुरा था, तो पत्नी ने कोई ब्याज नहीं लिया और अपीलकर्ता किसी भी बेहतर स्थिति में नहीं था। तैयबजी के मुहम्मडन कानून के तीसरे संस्करण में पृष्ठ 487 आदि में उस आधार पर भी चर्चा की गई है जिस पर हनब कानून के तहत जीवन हित का समर्थन किया जा सकता है: उस पुस्तक को एक लेखक के काम के रूप में अभी भी जीवित नहीं माना जा सकता है। प्राधिकारी, लेकिन उनके आधिपत्य ने चर्चा से सहायता प्राप्त की है।

शिया कानून के तहत 21 सीमित हितों को लंबे समय से मान्यता दी गई है। "हैब्स" का उद्देश्य "किसी व्यक्ति को संपत्ति के मालिक के अधिकार के आरक्षण के साथ किसी चीज़ का लाभ या उपभोग प्राप्त

करने के लिए सशक्त बनाना है...मैंने तुम्हें यह हवेली दी है...तुम्हारे जीवन के लिए या मेरा जीवन या एक निश्चित अवधि के लिए" प्राप्तकर्ता की ओर से जब्ती द्वारा बाध्यकारी है। (जमानत: II 226)। पृष्ठ पर 32 बॉम 1726 भी देखें। 179. उनके आधिपत्य का मानना है कि संपत्ति और स्वामित्व की उनकी मौलिक अवधारणा में मुस्लिम कानून के कई स्कूलों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी भी विद्यालय के अधीन उपभोग्य लाभ से सीमित ब्याज प्रभावी होता है। उनके आधिपत्य को इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम कानून के तहत उपहार से निपटने में, न्यायालय का पहला कर्तव्य उपहार का अर्थ लगाना है। यदि यह कोष का एक उपहार है, तो उपहार के विषय पर पूर्ण प्रभुत्व को कम करने वाली कोई भी शर्त प्रतिकूल के रूप में खारिज कर दी जाएगी, लेकिन यदि निर्माण के समय उपहार को सीमित हित में से एक माना जाता है तो उपहार प्रभावी हो सकता है सूदखोरी का, कॉर्पस के स्वामित्व को अप्रभावित छोड़ देना, सिवाय उस हद तक, जब तक इसका आनंद सीमित ब्याज की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है।"

(हमारा जोर है।)

14. प्रिवी काउंसिल द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों से उपरोक्त उद्धरण, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, कि उपहारों के लिए पैरामीटर (मोहम्मडन कानून के तहत) स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित हैं। संपत्ति के कोष से संबंधित उपहार पूर्ण हैं। जहां धन का उपहार समय के संदर्भ में (जीवन हित के रूप में) एक सीमा लगाने का प्रयास करता है, वह शर्त शून्य है। इसी तरह, कॉर्पस के उपहार में

अन्य सभी शर्तें अस्वीकार्य हैं। दूसरे शब्दों में, कॉर्पस का उपहार बिना शर्त होना चाहिए। हालाँकि, शर्तें स्वीकार्य हैं, यदि उपहार केवल उपभोग का है। इसलिए, सूदखोरी का उपहार वैध रूप से एक सीमा लगा सकता है, समय के संदर्भ में (ब्याज के रूप में, प्राप्तकर्ता के जीवन तक सीमित)।

15. हमारे ध्यान में लाए गए मुहम्मदन कानून के ग्रंथों और साथ ही नवाजिश अली खान के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए फैसले पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि एक उपहार में जो कॉर्पस के हस्तांतरण पर विचार करता है, ऐसे हस्तांतरण के सशर्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। स्थानांतरण पूर्ण है. निधि के उपहार में लगाई गई शर्तें शून्य हैं। वर्तमान विवाद के निर्धारण के लिए, हमारे द्वारा विचार किया जाने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या शेख हुसैन द्वारा बानू बीबी के पक्ष में 26.04.1952 को दिया गया उपहार कॉर्पस के हस्तांतरण पर विचार करता है। यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक है, तो दिनांक 26.04.1952 की वसीयत वैध मानी जाएगी, लेकिन उसमें शामिल शर्तें शून्य मानी जाएंगी।

16. कॉर्पस का हस्तांतरण स्वामित्व-जहाज में बदलाव को संदर्भित करता है, जबकि उपभोग का हस्तांतरण इसके उपयोग / आनंद आदि के अधिकार में बदलाव को संदर्भित करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या दिनांक 26.04.1952 के उपहार विलेख में हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है कॉर्पस के मामले में, हमें उपहार विलेख की सामग्री की जांच करनी होगी। तदनुसार, दिनांक 26.04.1952 का उपहार विलेख यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"अचल संपत्ति के हस्तांतरण का यह विलेख, यानी खुली जगह वाला टाइल वाला घर, मूल्य रु. 3000.00।

XXXXXXX

खपरैल वाला घर और खुली जगह नीचे दी गई अनुसूची में दिखाई गई है, जिसे मैंने अपनी कमाई से 16.7.1944 को श्रीमती से खरीदा था। माणिक्यम्मा, पत्नी श्री अरुंदलापल्ली तिरुवल्लुर वीरा राघवुलु और इसे दस्तावेज़ संख्या 2462/44 के रूप में पंजीकृत कराया और इसे अपने कब्जे में ले लिया और तब से यह मेरे पूर्ण अधिकार, कब्जे और आनंद के तहत है, इसमें कोई विवाद या कोई संयुक्त ज़मानत नहीं है। आदि। मैं आपके पक्ष में संदेश दे रहा हूं क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं और आपके प्रति प्रेम के कारण मैंने आपको इसका अधिकार दे दिया है। आपको तुरंत, अब से आप उपहार, बिक्री आदि के अधिकार के बिना इस अचल संपत्ति का स्वतंत्र रूप से आनंद लेंगे, और चूंकि आपके पास अब तक कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप अपने जीवन काल के दौरान संपत्ति का आनंद लेंगे। न तो मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी इस हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में आपके या आपके उत्तराधिकारियों के खिलाफ कोई आपत्ति उठाएंगे। हमें मूर्खतापूर्ण कारणों से इस परिवहन को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अपने जीवन काल के दौरान आप इस संपत्ति को किसी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं करेंगे और आपके जीवन काल के बाद यह संपत्ति आपके संतान होने पर हस्तांतरित हो जाएगी और यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो यह संपत्ति मुझे या मेरे निकटतम उत्तराधिकारियों को पूर्ण अधिकार के साथ वापस कर दी जाएगी। उपहार, बिक्री आदि के माध्यम से आनंद और बेदखली। मैं राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम परिवर्तित करने के लिए पंजीकरण के लिए इस विलेख के साथ स्थानांतरण ज्ञापन दाखिल कर रहा हूं। इसलिए अब

से आप नगरपालिका करों का भुगतान करेंगे और स्वतंत्र रूप से और खुशी से उसका आनंद उठाएंगे। मैंने आपको लिंक सेल डीड और वाउचर सौंप दिया है। यह तय हुआ कि उक्त वाउचर आपके जीवन काल के बाद मेरे पास या मेरे उत्तराधिकारियों के पास रहेगा।"

दिनांक 26.04.1952 के उपहार विलेख के पाठ पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि इसमें कॉर्पस के हस्तांतरण पर विचार किया गया है, न कि सूदखोरी पर। उपरोक्त निष्कर्ष के लिए हमारे कारण इस प्रकार हैं:

सबसे पहले, दाता रिकॉर्ड करता है कि उसने उपहार में दी गई संपत्ति को अपनी कमाई से 16.07.1944 को एक पंजीकृत खरीद विलेख के माध्यम से खरीदा था, जिसके तहत उसे संपत्ति के कब्जे और आनंद का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इसके बाद यह कहा गया कि उपहार में दी गई संपत्ति पर दाता के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। दाता के उपरोक्त सभी अधिकार, बानू बीबी को उपहार के माध्यम से यह कहते हुए हस्तांतरित करने की मांग की जाती है, "मैं आपके पक्ष में संदेश दे रहा हूं क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं और आपसे प्यार करते हैं और उसी का अधिकार आपको तुरंत सौंप दिया है।", अब से आप इसका आनंद लेंगे अचल संपत्ति स्वतंत्र रूप से..." यहां ऊपर दिए गए शब्द स्पष्ट रूप से उस निधि के हस्तांतरण को स्थापित करते हैं, जो दाता के प्राप्तकर्ता को पूर्ण स्वामित्व में था।

दूसरे, "हमें मूर्खतापूर्ण कारणों से इस हस्तांतरण को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं होगा" शब्दों के उपयोग से यह भी पता चलता

है कि दानकर्ता का संपत्ति की राशि प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करने का इरादा है।

तीसरा, शब्दों का प्रयोग "न तो मैं और न ही मेरे उत्तराधिकारी इस हस्तांतरित संपत्ति के संबंध में आपके या आपके उत्तराधिकारियों के खिलाफ कोई आपत्ति उठाएंगे", प्राप्तकर्ता के साथ-साथ उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। ये शब्द न केवल संपत्ति में दाता के, बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को भी समाप्त कर देते हैं। दान प्राप्तकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को इस हद तक मान्यता दी गई है कि उपहार में दी गई संपत्ति दान प्राप्तकर्ता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होने की स्थिति में दानकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। यह उपहार में दी गई संपत्ति के कोष को हस्तांतरित करने के दाता के इरादे को भी दर्शाता है।

चौथा, उपहार विलेख में दर्ज है कि"...आपके जीवन काल के बाद यह संपत्ति आपके वसंत ऋतु में हस्तांतरित हो जाएगी..."। "आपका ऑफ स्प्रिंग" शब्दों का उपयोग एक इरादे को व्यक्त करता है जो "हमारे ऑफ स्प्रिंग" से अलग और अलग है। दूसरे शब्दों में, उपहार विलेख उपहार में दी गई संपत्ति को प्राप्तकर्ता द्वारा अपने बच्चों को हस्तांतरित करने पर विचार करता है, भले ही ऐसे बच्चे दाता के बच्चे न हों। इससे यह भी पता चलता है कि दानकर्ता की मंशा, निधि के हस्तांतरण पर विचार करना था।

> पांचवें, उपहार विलेख में लिखा है, "मैं राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम परिवर्तित कराने के लिए पंजीकरण के लिए इस विलेख के साथ स्थानांतरण ज्ञापन दाखिल कर रहा हूं। इसलिए अब से आप नगरपालिका करों का भुगतान करेंगे और स्वतंत्र रूप से और खुशी से इसका आनंद लेंगे।" उपहार विलेख में यह अभिव्यक्ति, दाता के इरादे को उजागर करती है, कि उपहार में दी गई संपत्ति का हस्तांतरण परिवार के भीतर समझ का विषय नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनता के लिए एक खुली घोषणा होनी चाहिए। दावा उपहार विलेख में, कि नगरपालिका कर दान लेने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, यह दर्शाता है कि दान प्राप्तकर्ता को इसके मालिक के रूप में, उपहार में दी गई संपत्ति की सभी देनदारियों को वहन करना होगा।

अंत में, उपहार विलेख में यह दर्ज करके कि "मैंने लिंक बिक्री विलेख और वाउचर आपको सौंप दिया है" उपहार में दी गई संपत्ति के पहले स्वामित्व विलेख को प्राप्तकर्ता को सौंपना भी इंगित करता है, कि दाता ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है उपहार विलेख, कि उसने उपहार में दी गई संपत्ति से संबंधित स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज अपने पास नहीं रखा था, बल्कि उसे प्राप्तकर्ता को सौंप दिया था। यह उपहार में दी गई संपत्ति में अपने सभी मौजूदा अधिकारों को त्यागने के दाता के इरादे को भी दर्शाता है। यह दाता के इरादे को भी दर्शाता है, संपत्ति के कोष को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना।

यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है, कि 26.04.1952 के उपहार विलेख में दाता का इरादा, अचल संपत्ति के कोष को प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करना था, न कि केवल उसमें एक सूदखोर।

17. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि दाता शेख हुसैन ने उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 के माध्यम से, अचल संपत्ति का कोष अपनी पत्नी बानू बीबी को हस्तांतरित कर दिया था, यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि बानू बीबी के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख वैध था।. इसी तरह, मान्यता प्राप्त ग्रंथों में व्यक्त मुहम्मदन कानून के सिद्धांतों को लागू करते समय, और नवाज़िश अली खान के मामले (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को लागू करना अपरिहार्य है, कि उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 में दर्शाई गई सभी शर्तें, जो कम हो जाती हैं उपहार में दी गई संपत्ति का उपयोग या निपटान शून्य माना जाएगा। मामले के उपरोक्त दृश्य में, उपहार विलेख में दर्शाई गई शर्तें, कि दान प्राप्तकर्ता को उपहार में दी गई संपत्ति को उपहार में देने या बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा, या दान प्राप्तकर्ता को उसके जीवन काल के दौरान उपहार में दी गई अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका जाएगा, शून्य हैं. इसी प्रकार, उपहार विलेख में यह दर्शाया गया है कि उपहार प्राप्त करने वाले की मृत्यु के बाद उपहार में दी गई अचल संपत्ति, प्राप्तकर्ता की मृत्यु के बाद, उसे हस्तांतरित हो जाएगी और उस पर कोई भार न होने की स्थिति में संतान, वह दाता या उसके उत्तराधिकारियों को वापस लौटा दी जाएगी, वैसे ही शून्य हो जाएगी।

18. यह मानने के बाद कि उपहार विलेख दिनांक 26.04.1952 ने बानू बीबी की अचल संपत्ति में अपरिवर्तनीय रूप से सभी अधिकार निहित किए हैं, हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि बानू बीबी द्वारा उपहार में दी गई अचल संपत्ति की बिक्री 02.05.1978 को वी. श्रीरामचंद्र अवधानी को की गई थी। कानूनी और वैध था। नतीजतन, 17.02.1989 को बानू बीबी के निधन पर उपहार में दी गई संपत्ति पर उत्तरदाताओं का दावा कानून में टिकाऊ नहीं है।

19. यहां ऊपर दर्ज कारणों से तत्काल अपील की अनुमति दी जाती है। ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 19.08.1998 को पारित आदेश की पुष्टि की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2004 और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2004 को पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं।

20. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

विभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।